बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 24 ● अंकः 222 ● नई दिल्ली ● शनिवार 20 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन बी-2/370, सुल्तानपुरी दिल्ली-86

दिल्ली को मिला पहला महिला पुलिस स्टेशन, जांच अधिकारी से सिपाही तक सब महिलाएं

नई दिल्ली। राजधानी में पहली बार पूर्णकालिक महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। उत्तर दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में शुक्रवार को इस महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा की उपस्थिति में सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन परिसर में महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल संधु ने कहा कि यह महिला पुलिस स्टेशन राजधानी की महिलाओं की समस्याओं को सुनने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने का सीधा मंच बनेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य जिलों में भी ऐसे महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उपराज्यपाल ने यह भी घोषणा की कि शनिवार से सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत जन शिकायतों को सुनेंगे।

नीट -रीएग्जाम- टेलीग्राम पर 22 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध, दिल्ली हाईकोर्ट का बैन हटाने से इनकार

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा के कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। जिससे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस तेजस कारिया ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस तेजस कारिया ने आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। केंद्र सरकार ने 16 जून को नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी बैन लगा दिया था।

आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफीद - केंद्र

केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिए हलफनामे में दावा किया कि टेलीग्राम का इस्तेमाल साइबर अपराध, परीक्षा पेपर लीक, आतंकवाद से जुड़े प्रचार और वित्तीय धोखाधड़ी में किया जा रहा है। केंद्र ने कहा, टेलीग्राम अपराधियों का पसंदीदा नेटवर्क है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया, हमने यह कार्रवाई अचानक नहीं की है।

टेलीग्राम को हमने कई मौके दिए थे। इस एप की संरचना ऐसी है कि इसमें कई बॉट व चैनल बनाए जा सकते हैं, जो नीट परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए नुकसानदायक जानकारी फैला सकते हैं। केंद्र ने बताया कि अन्य एप के मुकाबले टेलीग्राम क्लाउड के जरिये काम करता है, जबकि फेसबुक जैसे अन्य मंच के यूआरएल होते हैं। केंद्र ने टेलीग्राम को आतंकी गतिविधियों के लिए सबसे मुफीद व सुविधाजनक बताया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने बताया कि टेलीग्राम में तारीख, समय बदलना संभव होता है, साथ ही खाता डिलीट करने पर डाटा भी डिलीट हो जाता है, जबकि अन्य सुरक्षित एप में यह सब संभव नहीं होता।

सिर्फ प्रश्नपत्र ही नहीं, निजी डाटा भी हो सकता है लीक

केंद्र ने नीट परीक्षा को कानून-व्यवस्था का मुद्दा बताते हुए अदालत से कहा कि टेलीग्राम के जरिये सिर्फ पेपर नहीं, बल्कि निजी डाटा भी लीक हो सकता है। हाईकोर्ट ने पूछा, कुछ नागरिकों के नीट-यूजी दोबारा देने की वजह से 15 करोड़ टेलीग्राम उपयोगकर्ताओं के अधिकारों पर कैसे बंदिश लगाई जा सकती है। टेलीग्राम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलीलें रखीं, जबकि केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सरकार ने कहा, टेलीग्राम चैनलों का उपयोग लीक हुए प्रश्नपत्र, नकली प्रश्नोत्तर साझा करने व धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था । वहीं, कंपनी ने दावा किया- उसने नीट से जुड़े 900 से अधिक अवैध लिंक हटा दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मैनुअल मॉडरेशन के जरिये निगरानी कर रही है। केंद्र ने जवाब में नीट माफिया नामक चैनल का भी जिक्र किया है, जिसके 18,617 सब्सक्राइबर हैं।

जन सुविधा केंद्रों पर बढ़ा भरोसा, एक दिन में पहुंचे 14,792 लोग; 42 केंद्रों पर लगी रही लोगों की कतार

नई दिल्ली । दिल्ली में सरकारी योजनाओं, सेवाओं और समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए जन सुविधा केंद्रों को लेकर लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। 18 जून को राजधानी के 42 जन सुविधा केंद्रों पर कुल 14,792 लोगों ने पहुंचकर विभिन्न सेवाओं की जानकारी ली और अपनी जरूरतों से जुड़े मामलों का समाधान तलाशा। इनमें इंद्रपुरी के सर्वोदय विद्यालय केंद्र पर बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। जन सुविधा केंद्रों का उद्देश्य लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी व सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों को स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संचालित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में ही सरकारी योजनाओं तक पहुंच मिल सके। 18 जून के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के अलग-अलग इलाकों में संचालित केंद्रों पर हजारों नागरिक पहुंचे। इससे संकेत मिलता है कि स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्षेत्रवार आंकड़ों में इंद्रपुरी स्थित सर्वोदय विद्यालय जन सुविधा केंद्र पर 394 आगंतुक पहुंचे। इसके अलावा कई अन्य केंद्रों पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सेवाओं का लाभ लिया। जन सुविधा केंद्रों में आने वाले लोग पेंशन, प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे लोगों को विभागों के बीच समन्वय की परेशानी कम होने की उम्मीद है। इन केंद्रों की खास बात यह है कि प्रशासन ने लोगों तक पहुंच बनाने के लिए पहले से मौजूद सार्वजनिक ढांचे का इस्तेमाल किया है। दिल्ली के सभी जिलों में सरकारी स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में व्यवस्था होने से स्थानीय निवासियों को अपने इलाके से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। इस पहल से बुजुर्गों, महिलाओं और ऐसे लोगों को विशेष सुविधा मिल रही है, जिन्हें छोटे-छोटे सरकारी कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आंकड़ों के मुताबिक, कई केंद्रों पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रही।

ब्रह्मपुरी, ईस्ट लोनी रोड, करावल नगर, जनकपुरी, रोहिणी, नजफगढ़, पालम, मालवीय नगर, सागरपुर और अन्य क्षेत्रों में संचालित केंद्रों पर लोगों ने सेवाओं की जानकारी ली। इससे साफ है कि जन सुविधा केंद्र अब केवल सूचना केंद्र नहीं रह गए हैं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच संपर्क के अहम माध्यम बनते जा रहे हैं। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए आसानी से जानकारी और सहायता मिल सके। जन सुविधा केंद्रों की बढ़ती संख्या और लोगों की भागीदारी से यह व्यवस्था मजबूत हो रही है। एक दिन में करीब 15 हजार लोगों का इन केंद्रों तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि नागरिक अपने कामों के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सरकारी सहायता को प्राथमिकता दे रहे हैं।

जन कल्याण शिविर में पहुंचकर इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं - सीएम

वहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक दिल्लीवासियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से संदेश विहार स्थित एमसीडी कम्युनिटी हॉल में जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण की प्रेरणा से दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक राजधानी के 42 स्थानों पर जन कल्याण शिविर आयोजित कर रही है, जहां केंद्र एवं दिल्ली सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण एवं सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। सभी दिल्लीवासियों से आग्रह है कि अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं।

पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट बोला- फुटपाथ पर राहगीरों का हक सबसे पहले

नई दिल्ली । सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि निर्धारित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता मिलेगी। अदालत ने कहा कि सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथ उपलब्ध कराना सरकार और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। यह फैसला एक सड़क हादसे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें स्कूल जा रहे पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदूरकर की पीठ ने कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ख) के तहत मिले आवागमन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि यह अधिकार अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। पीठ ने साफ कहा कि सड़क पर चलने का सबसे पहला अधिकार पैदल यात्रियों का है और फुटपाथ उनके लिए सुरक्षित तथा संरक्षित होने चाहिए।

फुटपाथ बनाने और बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सड़क है तो उसके साथ सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथ भी होना चाहिए। अदालत के अनुसार शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाएं और पंचायतें फुटपाथ बनाने, उनकी देखरेख करने और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए जिम्मेदार हैं। अदालत ने कहा कि पैदल चलना जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इस बुनियादी सुविधा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

फुटपाथ का अधिकार टूटने पर क्या कर सकेंगे नागरिक?

अदालत ने कहा कि यदि किसी नागरिक के फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह संवैधानिक और कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकारों से अलग और स्वतंत्र होगा।

सड़क व्यवस्था को लेकर अदालत ने क्या बड़ी टिप्पणी की?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसान पहियों के आविष्कार से पहले से पैदल चलता आया है, लेकिन समय के साथ मोटर वाहनों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया और पैदल यात्रियों को हाशिये पर धकेल दिया गया। अदालत ने कहा कि कई बार पैदल यात्रियों को वाहन चालकों के लिए बाधा की तरह देखा जाता है और फुटपाथों पर भी अतिक्रमण हो जाता है। यह स्थिति अब बदलनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विधि आयोग को भी इस संबंध में जरूरी कानूनी ढांचा तैयार करने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। साथ ही मृत बच्चे के पिता को मिलने वाला मुआवजा बढ़ाकर 11.44 लाख रुपये कर दिया गया।

मालवीय नगर अग्निकांड के नायक रोहित को सम्मान, सीएम रेखा गुप्ता ने दिए 5 लाख और मुफ्त इलाज का भरोसा

नई दिल्ली । मालवीय नगर के हौज रानी स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग के दौरान कई लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया के साहस को दिल्ली सरकार ने विशेष सम्मान दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहित के परिवार को तत्काल 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ यह भी घोषणा की है कि उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री ने रोहित को एक भावनात्मक पत्र भेजकर उनके साहस की सराहना की और जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए पत्र में रोहित के घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी रोहित ने धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखी. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में दिल्ली सरकार रोहित और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. उन्होंने रोहित के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पश्चिमी दिल्ली के जिलाधिकारी ने रोहित के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की. इस दौरान 5 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा गया. प्रशासन की ओर से परिवार को भरोसा दिलाया गया कि उपचार और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. 3 जून को मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई थी. उस समय रोहित मुखिया रेस्टोरेंट के किचन में ड्यूटी कर रहे थे. आग फैलते ही उन्होंने सबसे पहले अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया. उनके गांव के दो साथी भवन की पहली मंजिल पर फंसे हुए थे. हालात की गंभीरता को देखते हुए रोहित बिना अपनी जान की परवाह किए उन्हें बचाने के लिए ऊपर पहुंच गए. अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने वाले रोहित मुखिया की बहादुरी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने संदेश में कहा कि रोहित ने कर्तव्य और इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है।

महिलाओं की सुरक्षा पर एनसीडब्ल्यू सख्त - हर साल पॉश ऑडिट कराने की सिफारिश, कहा-गरिमा और नौकरी में न करना पड़े चुनाव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की। आयोग ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देने के लिए हर साल पॉश ऑडिट कराना अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए POSH कानून, 2013 के नियमों को सख्ती से लागू करने के कई सुझाव दिए गए हैं। यह सलाह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजी गई है। जमीनी स्तर पर प्रवर्तन और जवाबदेही के लिए इसे देश भर के जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को भी वितरित किया गया है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा 'किसी महिला को कभी भी अपनी गरिमा और आजीविका के बीच चुनाव नहीं करना चाहिए। हर कार्यस्थल सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर का स्थान होना चाहिए।' एक बयान में आयोग ने कहा कि इस सलाह का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कार्यस्थल, चाहे वह सरकारी हो, निजी हो, संगठित हो या असंगठित क्षेत्र का हो, उत्पीड़न (कार्यस्थल पर महिलाओं का) रोकथाम (पॉश) अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करे और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और लिंग-संवेदनशील कार्य वातावरण को बढ़ावा दे।

आगे कहा गया है कि संस्थागत जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीओएसएच अधिनियम के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए समर्पित पीओएसएच निगरानी प्रकोष्ठ या डिजिटल अनुपालन डैशबोर्ड स्थापित करने की सलाह दी है। राज्यों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे वरिष्ठ प्रशासनिक स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा करें, क्षमता निर्माण को सुगम बनाएं, प्रतिष्ठानों और जिला अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन जारी करें और वैधानिक दायित्वों और न्यायिक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। इस परामर्श में 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य वार्षिक पॉश ऑडिट की सिफारिश की गई है। आयोग ने कहा कि ऑडिट में कानूनी अनुपालन, आंतरिक समितियों के कामकाज, शिकायतों की स्थिति, गोपनीयता सुरक्षा उपाय, कार्यस्थल सुरक्षा अवसंरचना, जागरूकता पहल, अनिवार्य खुलासे और SHe-Box प्लेटफॉर्म के उपयोग का आकलन किया जाएगा इसमें कहा गया है, ऑडिट रिपोर्ट जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को प्रस्तुत की जानी है। ऑडिट न करना गैर-अनुपालन माना जाएगा। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि प्रत्येक आंतरिक समिति का गठन कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिसमें एक महिला अध्यक्ष, योग्य सदस्य, एक बाहरी विशेषज्ञ और कम से कम 50 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिला अधिकारियों को अनुपालन रिपोर्टों और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा करने, गैर-अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान करने, आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने और जमीनी स्तर पर सतत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गहन पीओएसएच जागरूकता अभियान चलाने का कार्य सौंपा गया है।

सम्पादकीय...

संघर्ष की ओर बढ़ रहा है मध्य-पूर्व?

मध्य-पूर्व एक बार फिर तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। इज़राइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के नेतृत्व में हाल के सैन्य हमलों ने क्षेत्रीय राजनीति को नई उथल-पुथल में डाल दिया है। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर इज़राइली हमलों और ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि क्षेत्र में शांति की राह अभी भी कठिन बनी हुई है। हालिया घटनाओं में इज़राइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और दक्षिणी लेबनान में कई सैन्य अभियान चलाए हैं, जिन्हें वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक बता रहा है। इज़राइल का तर्क है कि हिज़्बुल्लाह और ईरान समर्थित संगठनों की ओर से लगातार हो रहे हमले उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा है कि इज़राइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हर कदम उठाएगा और किसी भी हमले का और अधिक कठोर जवाब देगा। लेकिन दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि लगातार सैन्य कार्रवाई से संघर्ष और अधिक गहरा हो रहा है। लेबनान में हो रहे हमलों से आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, विस्थापन बढ़ रहा है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सैन्य शक्ति वास्तव में स्थायी शांति ला सकती है? हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी हुए हैं। एक नए समझौते और युद्धविराम की संभावनाओं के बीच इज़राइली हमलों ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी नेतृत्व ने क्षेत्र में व्यापक युद्ध से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जबकि इज़राइल ने अपने सुरक्षा हितों को सर्वोपरि बताया है। यह स्थिति दर्शाती है कि मध्य-पूर्व में केवल सैन्य शक्ति से समाधान निकालना आसान नहीं है। यदि कूटनीतिक प्रयास कमजोर पड़ते हैं, तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है। मध्य-पूर्व केवल क्षेत्रीय राजनीति का विषय नहीं है। यह दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से भी जुड़ा हुआ है। जब भी इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है और विश्व अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। इज़राइल, लेबनान, ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ता संघर्ष वैश्विक बाजारों के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा होता है। इसलिए क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता का असर भारतीय अर्थव्यवस्था, तेल आयात और विदेश नीति पर पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू की रणनीति केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक आयाम भी हैं। इज़राइल में चुनावी और आंतरिक राजनीतिक दबावों के बीच मजबूत नेतृत्व की छवि बनाए रखना भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने से नहीं हिचकते। वहीं विरोधियों का आरोप है कि लगातार सैन्य कार्रवाई क्षेत्र को स्थायी शांति से दूर ले जा रही है। इतिहास बताता है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। सैन्य कार्रवाई कुछ समय के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन दीर्घकालिक शांति के लिए संवाद, विश्वास और कूटनीति आवश्यक हैं। इज़राइल और उसके पड़ोसियों के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष ने हजारों लोगों की जान ली है और लाखों लोगों को प्रभावित किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी पक्ष संयम बरतें और वार्ता के रास्ते को मजबूत करें। यदि सैन्य टकराव बढ़ता है, तो इसका दुष्परिणाम केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व को उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नेतन्याहू द्वारा किए गए हालिया हमले एक बार फिर यह याद दिलाते हैं कि मध्य-पूर्व में शांति अभी भी एक दूर का लक्ष्य है। इज़राइल अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला दे रहा है, जबकि उसके विरोधी इसे आक्रामक नीति मान रहे हैं। सच चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट है–युद्ध का विस्तार किसी के हित में नहीं है। क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवता के हित में यही आवश्यक है कि संघर्ष की जगह संवाद को प्राथमिकता दी जाए। तभी मध्य-पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीद की जा सकती है।

'370 की बिरयानी'..हास्य है या 'मानसिक गंदगी'

मनोरंजन मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल समय बिताने का साधन नहीं है बल्कि मन को हल्का करने, तनाव कम करने और सकारात्मक ऊर्जा देने का माध्यम भी है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन का स्वरूप तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। आज के समय में फिल्मों, वीडियो, सोशल मीडिया, कॉमेडी कार्यक्रमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सामग्री बढ़ती जा रही है जिसे कई लोग मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता के रूप में देखते हैं। यह केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी के संस्कारों से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न भी है। कुछ क्रिएटर यह सोचते हैं कि इसी से उन्हें लोकप्रियता और पैसा मिल रहा है, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं और उसके प्रभाव से पूरी तरह अलग नहीं रह सकते। जब मनोरंजन अपनी मर्यादा खोने लगे और उसमें अशोभनीय भाषा, द्विअर्थी संवाद या अनुचित दृश्य शामिल होने लगें, तब वह केवल मनोरंजन नहीं रह जाता बल्कि समाज के सामने एक सांस्कृतिक चुनौती बन जाता है। इस विषय पर गंभीरता से विचार करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मनोरंजन का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ता है, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं पर। सोशल मीडिया ने सिर्फ समाज और भाषा की मर्यादा को ही तार-तार नहीं किया है, बल्कि इसने समाज के नैतिक मूल्यों को भी चोट पहुंचाई है। ये अनियंत्रित सोशल मीडिया मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। इसमें सिर्फ ट्रोल्स ही शामिल नहीं हैं, इसमें वो स्टैंड-अप कॉमेडियन भी शामिल हैं जो अश्लीलता को कॉमेडी का रूप देकर प्रजेंट कर रहे हैं। गुरुग्राम में हुए स्टैंड-अप कॉमेडी शो में '370 की बिरयानी' वाले विवाद पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर होस्ट प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा पर कानूनी डंडा चलाया है। बता दें कि प्रणीत मोरे का शो तो कॉमेडी और 'एंटरटेनमेंट' का था लेकिन अफसोस आजकल के कॉमेडियन कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसते नजर आते हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पर औरतों के सम्मान को सरेआम नीलाम करते हैं। हिमांशु जांगड़ा ने '370 की बिरयानी' के बदले शारीरिक संबंध की मांग जैसी बेहद आपत्तिजनक बात कही। पर उससे भी ज्यादा शर्मनाक था होस्ट प्रणीत मोरे का रिएक्शन रोकने की बजाय शाबाशी दी, और ऊपर से 5000 रुपये का इनाम भी थमा दिया। नये विवाद के केंद्र में एक मेडिकल छात्रा सेजल पवार हैं। वह मुंबई में एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा हैं। लगभग तीन महीने पुराने शो में होस्ट प्रणीत मोरे क्राउड वर्क के दौरान सेजल से बात करते हैं। वह उनसे एनाटॉमी और पोस्टमार्टम पर सवाल कर रहे थे। सेजल बता रही हैं कि शवों की मेडिकल जांच कैसे होती है। इस बीच वह कहती हैं कि डॉक्टर कई बार मृत पुरुषों के जननांगों को लेकर मज़ाक करते हैं। जब वह यह बात कर रही थीं तब भी प्रणीत ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि हंसते हुए ठहाके लगाते रहे। यह वीडियो क्लिप तब वायरल नहीं हुई, बल्कि हिमांशु प्रकरण के बाद तेजी से फैली। सोशल मीडिया पर सेजल पवार की इस टिप्पणी को लेते हुए यूजर सवाल करने लगे कि वह तो मेडिकल प्रोफेशन से है। जब वह शवों तक का सम्मान नहीं करेंगी तो मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। यहां तक कि कई यूजर उन्हें मेडिकल कॉलेज से निकालने तक की मांग तक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि मेडिकल छात्रों के अध्ययन के लिए शरीर दान करने वाले मृतकों तक की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा। इस बीच, मुंबई के केईएम अस्पताल, जहां सेजल पढ़ रही हैं, उसका प्रशासन भी हरकत में आ गया। अस्पताल की ही दो सदस्यीय कमेटी वीडियो क्लिप की समीक्षा कर रही है और सेजल को छुट्टी पर भेज दिया गया है। स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, उनके शो में शामिल हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इन सभी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए अश्लील, आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश और शेयर करने का आरोप है। वहीं इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 75(3), 294, 353(2) लगाई गई है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 भी लगाई गई है। चीन के फेमस फिलोसफर कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जिस समाज में मनोरंजन का लेवल गिर जाता है वहां कला बेकार हो जाती है और लोग अपनी मर्यादा खो देते हैं। प्रणीत मोरे जैसे लोग अपने अपराध को स्टैंड-अप कॉमेडी और मनोरंजन का नाम देते हैं। इसे कला बताते हैं लेकिन ये कला नहीं है, ये फूहड़ता है। ये उनकी सोच, समझ और गलत विचार का प्रमाण है। दोषी सिर्फ ये नहीं हैं..दोषी हमें सुनने वाले भी हैं। फरवरी 2025 में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में रणवीर अल्लाहबादिया ने एक कंटेस्टेंट से माता-पिता और उनके निजी जीवन को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अश्लील सवाल पूछ लिया था। शो में अपूर्वा मखीजा भी थीं। इस भद्दे मज़ाक को बढ़ावा देने के कारण लोग भड़क गए थे। अश्लीलता फैलाने के आरोप में असम (गुवाहाटी) और दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई थी और शो के उस एपिसोड को यूट्यूब से हटाना पड़ा था। सिर्फ यही नहीं, इन इंफ्लुएंसर्स के हाथ से कई ब्रैंड डील्स भी छिन गई थीं। बदलते समय के साथ समाज को कुछ विषयों पर खुलकर और जिम्मेदारी के साथ चर्चा करनी होगी। विशेष रूप से युवाओं को सही दिशा देने के लिए जीवन मूल्यों, रिश्तों, जिम्मेदारियों और यौन शिक्षा जैसे विषयों पर संतुलित और वैज्ञानिक संवाद आवश्यक है। यदि समाज इन विषयों पर मौन रहेगा तो युवा जानकारी के लिए ऐसे स्रोतों की ओर जाएंगे जो हमेशा सही दिशा नहीं देते। यदि हम उन्हें संवेदनशीलता, सम्मान, संस्कार और मानवीय मूल्यों का महत्व सिखाएंगे तो समाज भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अंत में यह आवश्यक है कि किसी भी एक व्यक्ति, कलाकार या युवा को दोष देने की नहीं है। आवश्यकता है आत्ममंथन की। हमें यह विचार करना होगा कि हम अपने परिवारों, समाज और आने वाली पीढ़ियों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हास्य होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही मानवीय गरिमा, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी भी बनी रहनी चाहिए। यही संतुलन किसी भी सभ्य समाज की पहचान है।

कूटनीति का नया अध्याय

प्रधानमंत्री मोदी का हालिया यूरोप दौरा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के साथ-साथ जी-7 शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को एक बार फिर रेखांकित किया है। यह दौरा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यापार, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा सहयोग और वैश्विक चुनौतियों पर भारत की सक्रिय भागीदारी का महत्वपूर्ण संदेश भी लेकर आया। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति अनेक चुनौतियों से गुजर रही है, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत की कूटनीतिक सक्रियता और रणनीतिक सोच का परिचायक माना जा रहा है। फ्रांस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत को लगातार आठवीं बार आमंत्रित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि विश्व समुदाय भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार के रूप में देख रहा है। इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव फ्रांस रहा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति Emmanuel Macron के साथ व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और फ्रांस के बीच पहले से ही मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, जिसे इस यात्रा ने और अधिक मजबूती प्रदान की है तकनीकी क्षेत्र में भी यह दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित विवाटेक 2026 सम्मेलन में भारत को वैश्विक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रमुख केंद्र बताया। उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों और तकनीकी कंपनियों को भारत में निवेश करने और साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और नवाचार आधारित विकास मॉडल को उन्होंने भारत की ताकत के रूप में प्रस्तुत किया। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई प्रमुख फ्रांसीसी उद्योगपतियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इन बैठकों का उद्देश्य भारत में निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और नई तकनीकों को भारत तक लाना था। वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में विदेशी निवेश भारत की विकास गति को और तेज कर सकता है। इस यात्रा का एक और उल्लेखनीय पक्ष स्लोवाकिया दौरा रहा। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस ऐतिहासिक दौरे ने मध्य यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को नया आयाम दिया। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, रक्षा और तकनीकी सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई। जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय शांति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भारत का दृष्टिकोण रखा। भारत ने विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाने का प्रयास किया और यह संदेश दिया कि वैश्विक समस्याओं का समाधान सामूहिक सहयोग से ही संभव है। यूरोप दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत-यूरोप व्यापार संबंध भी रहा। भारत और यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते तथा निवेश सहयोग को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। यदि ये प्रयास सफल होते हैं तो भारतीय उद्योग, निर्यात और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि विपक्ष और कुछ आलोचक विदेश यात्राओं की उपयोगिता पर प्रश्न उठाते रहे हैं, लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थितियों में कूटनीतिक संवाद और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत को आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास माना जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया

पश्चिम वास्तव में, 1947 से ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के नाम देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज था। उन्होंने करीब 17 वर्षों से कुछ कम समय तक प्रधानमंत्री पद संभाला, सटीक रूप से कहें तो 4398 दिनों तक। इसे एक रिकॉर्ड के रूप में देखा जाता था, जिसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी का 4077 दिनों का कार्यकाल इस सूची में शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मोदी के कार्यकाल की यह गणना नेहरू के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 1951-52 के पहले आम चुनाव के बाद के कार्यकाल से की जाती है, जिसमें उनके शुरुआती गैर-निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में बिताए गए समय को शामिल नहीं किया गया है। इसी आधार पर दिन की गणना की जाती है। नेहरू के 4398 लगातार दिनों के रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह की शुरुआत में पद पर लगातार 4399 दिन पूरे कर पार कर लिया। मोदी के समर्थक इसे कई उपलब्धियों और पड़ावों के साथ जोड़ते हैं। पिछले वर्ष ही मोदी ने इंदिरा गांधी के 4077 लगातार दिनों तक प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। उस समय पार्टी ने इसे 'रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों' के रूप में प्रस्तुत किया था। इनमें कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं, श्री मोदी भारत की स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री हैं; वे गैर-हिंदी भाषी राज्य से आने वाले सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं और वे भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी प्रमुख के रूप में लगातार छह चुनाव जीते हैं, इनमें तीन राज्य विधानसभा चुनाव और तीन लोकसभा चुनाव शामिल हैं। बेशक, एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जिसे श्री मोदी अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं और जिसे तोड़ने की उनकी इच्छा अवश्य होगी। वह है जवाहरलाल नेहरू का लगभग 17 वर्षों तक

प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड। इस गणना में भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनका शुरुआती 'गैर-निर्वाचित कार्यकाल' भी शामिल किया जाता है। यह बात अब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर सरकार के शीर्ष नेतृत्व में-नेहरू को लेकर एक विशेष आग्रह मौजूद है। यही कारण है कि जब कांग्रेस सांसद ने संसद में कहा था कि भाजपा को इस मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए, तो उनका तर्क एक हद तक उचित था।

वर्ष 2025 में ही प्रियंका गांधी ने संसद में कहा था, 'नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की हैं' जितनी भी गालियां देनी हैं, जितना भी अपमान करना है, एक सूची बना दीजिए। 999 अपमान, 9099 अपमान, जितनी भी शिकायतें हैं, उनकी सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित कर लेते हैं, 10 घंटे, 20 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायतें पूरी हो जाएं। हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय जिसका इस्तेमाल इसी जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा में करना चाहिए, उसे इसी विषय में हमेशा के लिए इस्तेमाल न करें। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं -'एक बार और हमेशा के लिए इस अध्याय को समाप्त कर दें। सुन लीजिए, फिर खत्म कर दीजिए उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करें। प्रियंका गांधी ने यह बात एक मजबूत तर्क के साथ रखी थी।

बार-बार, चाहे संसद के भीतर हो या बाहर, सार्वजनिक सभाओं में हो या चुनावी अभियानों के दौरान, भाजपा का मुख्य राजनीतिक हमला यही रहा है कि नेहरू-गांधी परिवार ने क्या गलतियां कीं, कैसे उन्होंने जानबूझकर धीरे-धीरे देश को नुकसान पहुंचाया। कैसे उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और कैसे देश उन क्षेत्रों में भी पीछे रह गया जहां उसे आगे बढ़ना चाहिए था। इसके साथ ही इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल और एक अर्थ में लोकतंत्र का गला घोंटने के आरोप को भी बार-बार उठाया जाता रहा है। यह कहने के बाद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद कांग्रेस लंबे समय तक देश की एकमात्र अखिल भारतीय पार्टी बनी रही। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के 4399 दिनों के कार्यकाल ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। भाजपा अब उस लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी है, बल्कि कई मायनों में उसने वह मुकाम हासिल भी कर लिया है।

आज विपक्ष बिखरा हुआ है और राष्ट्रीय नीतियों या कार्यक्रमों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता खो चुका है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी बहुमत वाली सरकारें चलाई थीं, लेकिन उस समय विपक्ष उतना निष्प्रभावी नहीं था, जितना आज है जबकि वर्तमान में मोदी की पार्टी के पास लोकसभा में केवल 240 सदस्य हैं। इस लिहाज से भाजपा एक तरह से नेहरू युग को दोहरा रही है, क्योंकि उनके शासनकाल में भी विपक्ष का प्रभाव सीमित था। संख्या मौजूद थी, लेकिन आवाज कमजोर थी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मोदी की व्यक्तिगत छवि ने बाकी सभी मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है और क्षेत्रीय दल अपनी जगह तलाशने में लगे हुए हैं।

अगर पश्चिम बंगाल में एक समय की संघर्षशील और आंदोलनकारी नेता ममता बनर्जी को भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, तो यह सभी क्षेत्रीय दलों के लिए एक स्पष्ट संकेत है। यहां तक कि 'हमारा बंगाल' की अवधारणा पर गर्व करने वाले लोग भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने बदलाव लाने में भूमिका निभाई। इस मुद्दे पर उनका तर्क सही भी है। मोदी की राजनीति को लेकर किसी के भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था का मॉडल चर्चा का विषय रहा है और कई बार इसे उनकी सरकार की बड़ी ताकत के रूप में देखा गया है। निश्चित रूप से इसमें कमियां भी हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में कुछ चुनौतियों का होना स्वाभाविक है। महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई मोदी सरकार की राजनीति और नीतियों का जमीन पर प्रभाव दिखाई दिया है। शौचालय, व्यक्तिगत बैंक खाते और घरों के स्वामित्व जैसी सुविधाओं के साथ महिलाएं भाजपा, यानी मोदी के लिए एक मजबूत मतदाता वर्ग के रूप में उभरी हैं। समय सीमा के आधार पर पूरी की जाने वाली परियोजनाएं भी मोदी सरकार के पक्ष में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रही हैं। वह दौर पीछे छूट गया जब परियोजनाओं की आधारशिला रख दी जाती थी, लेकिन वे दशकों तक अधूरी पड़ी रहती थीं। मोदी के व्यक्तिगत प्रयास और दृढ़ संकल्प ने यह दिखाया है कि वे और उनकी सरकार लगातार काम करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिखाई गई ऊर्जा उल्लेखनीय रही है। हालांकि समय सीमा में पूरी की गई परियोजनाओं को लेकर भी समस्याएं सामने आई हैं पुलों का गिरना और हवाई अड्डों की छतों का उड़ जाना इसके उदाहरण हैं। लेकिन इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है और मोदी सरकार को इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

विश्व मंच पर भी मोदी ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। आज जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। आज मोदी ऐसे नेता हैं जिन्हें दुनिया अच्छे और बुरे, दोनों कारणों से नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच के केंद्र में ला खड़ा किया है। कोई यह तर्क दे सकता है कि यह केवल छवि निर्माण है और इसमें वास्तविकता की कमी है। संभव है, लेकिन आम नागरिक के नजरिए से ये बड़े बदलाव हैं। मोदी सरकार को अपनी सकारात्मक उपलब्धियों को और मजबूत करने के साथ-साथ नकारात्मक पहलुओं को कम करने की दिशा में काम करना होगा। तभी प्रधानमंत्री के रूप में बिताए गए दिनों की यह संख्या वास्तविक मायने रखेगी और लंबे समय तक प्रभावी साबित होगी।

नव-उदारवाद का संकट - मर्ज़ बढ़ता ही गया यों-यों दवा दी उनने

नव-उदारवाद के प्रवक्ताओं की एक बात बहुत खास होती है। जब भी नव-उदारवाद पर अमल के चलते कोई अर्थव्यवस्था संकट में फंस जाती है, वह एक ही रामबाण उपचार बताते हैं और ज्यादा नव-उदारवादी 'सुधार' किए जाएं। यह सबसे स्वतःस्पष्ट रूप में सोवियत संघ के पराभव के बाद रूस में देखने को मिला था। जैसे-जैसे नव-उदारवादी 'सुधार' रूसी अर्थव्यवस्था को संकट में गहरे से गहरा धंसाते गए, वैसे-वैसे हरेक चरण में 'सुधारवादी' यही सुझाते रहे कि और ज्यादा 'सुधार' किए जाएं। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि देश की अर्थव्यवस्था ही मुट्ठीभर धनकुबेरों के हाथों में नहीं आ गयी और मेहनतकश जनता के जीवन स्तर में एक सत्यानाशी शुद्ध गिरावट नहीं हो गयी। व्लादीमीर पुतिन के बारे में हम चाहे जो भी सोचते हों, आखिरकार उन्हीं ने अर्थव्यवस्था को धनकुबेरों के शिकंजे से बाहर निकला था। ऐसा ही दृश्य आज भारत में देखने में आ रहा है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट की जकड़ में है। इस संकट की अभिव्यक्ति सबसे बढ़कर रुपए के विनिमय मूल्य में भारी गिरावट और मुद्रास्फीति के तेज होने में हो रही है। रुपए का यह अवमूल्यन, हालांकि पिछले कुछ समय में इसमें इसने और तेजी पकड़ी है, एक लंबे अर्से से जारी परिघटना है। वास्तव में इसकी शुरुआत तो तभी हो गयी थी, जब नव-उदारवाद के तकाजों के अनुरूप रुपए को विनिमय मूल्य के मामले में तैरता छोड़ दिया गया था। 1992-93 में, रुपए को तैरता छोड़े जाने के फौरन बाद, एक डालर का मूल्य 22.74 रुपये के बराबर था। 2024 के आखिर में एक डालर का मूल्य 85.47 रुपये पर पहुंच चुका था और आज एक डालर 95 रुपये से ऊपर जा चुका है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में, जो कमोबेश साल दर साल अपने भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटे में चल रही हो, मुद्रा का तैरता छोड़ा जाना, सीधे-सीधे यही सुनिश्चित करता है कि संबंधित मुद्रा का मूल्य नीचे से नीचे ही खिसकता जाए, जैसा कि वास्तव में हुआ भी। रुपए की विनिमय दर को तैरता छोड़े जाने से पहले के लंबे दौर में, रुपए की विनिमय दर एक स्तर पर बांध कर रखी जा रही थी और उस दौर में विदेशी मुद्रा बाजार की पहचान राशनिंग से होती थी। साफ है कि नव-उदारवादी सुधारों के ही चलते, जिनका तकाजा था कि रुपए के विनिमय मूल्य को तैरता हुआ छोड़ दिया जाए, रुपए के विनिमय मूल्य में यह आम गिरावट भी आयी है और पिछले ही दिनों में आयी वह और भी तेज गिरावट भी, जो और भी हाल की विशेष परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें ट्रंप के टैरिफ और ईरान के खिलाफ युद्ध शामिल हैं। इसके बावजूद, वर्तमान संकट के समाधान के रूप में और ज्यादा 'सुधार' की मांग का समूह गान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीति आयोग के सदस्यों तक और सरकारी तथा गैर-सरकारी अर्थशास्त्रियों की लंबी कतार तक, एक ही दलील सुनने को मिल रही है कि निजी तथा खासतौर पर विदेशी पूंजी को, उस पर हमारे देश में जो बची-खुची पाबंदियां रह भी गयी हैं, उनसे भी आजाद करा दिया जाना चाहिए और सभी संभव उपायों से उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भारत में आएं, ताकि इस देश को संकट से उबार सकें। आइए, इस दलील की जरा सावधानी से पड़ताल करते हैं। जब तक किसी देश में चालू खाता घाटा बने रहने की प्रवृत्ति रहती है, उसकी विनिमय दर के संबंध में आम प्रत्याशा गिरावट होने की ही रहती है। बेशक, संबंधित अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रवाह आ रहे हो सकते हैं, जिससे केंद्रीय बैंक के विनिमय दर में बढ़ोतरी से बचने के प्रयास के साथ, विदेशी मुद्रा संचित कोष भी जमा हो सकता है। फिर भी सटोरिये अगर बिल्कुल ही आंखों के अंधे नहीं होंगे तो वे यह मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि संबंधित अर्थव्यवस्था में चालू खाता घाटा बराबर बने रहने के बावजूद, चालू विनिमय दर हमेशा के लिए जहां की तहां बनाए रखी जा सकती है। उस तरह का भरोसा करने का मतलब तो उनका विश्वासपूर्वक यह मानना होगा कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, संबंधित देश में आने वाले वित्तीय प्रवाह हमेशा ही चालू खाता घाटे को पाटने के लिए जरूरी वित्त प्रवाहों से फालतू ही बने रहेंगे। और ऐसा होने की संभावना करीब-करीब नहीं के बराबर होगी। अगर कुछ समय तक वित्त के प्रवाह, चालू खाता घाटे की भरपाई करने लिए जरूरी वित्त से ज्यादा बने रहते हैं तथा इसके चलते कुछ विदेशी मुद्रा कोष जमा भी हो जाता है, तब भी कोई भी ऐसा आकस्मिक घटना विकास जिसके चलते वित्तीय प्रवाह, उक्त घाटे की भरपाई करने के लिए आवश्यक स्तर से कम हो जाएं, विनिमय दर को नीचे ले आएगा। संबंधित देश का केंद्रीय बैंक इसे रोक नहीं पाएगा क्योंकि वह अपने विदेशी मुद्रा संचित कोष से विदेशी मुद्रा निकालने में झिझकेगा। क्योंकि इससे ऐसी प्रत्याशाएं भड़कने का डर होगा, जिनके चलते वित्त का पलायन शुरू हो सकता है। और एक बार जब विनिमय दर में गिरावट शुरू हो जाती है, सटोरियों को यह उम्मीद लग जाएगी कि आगे और अवमूल्यन होगा। और ऐसी प्रत्याशाओं के साथ, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां चालू खाता घाटा लगातार बना रहता हो, अगर विनिमय दर को तैरता छोड़ दिया गया हो, मुद्रा का लगातार अवमूल्यन होना अपरिहार्य है। विनिमय दर को तैरता छोड़ने के पैरोकार यह दलील दे सकते हैं कि विनिमय दर को तैरता छोड़ने का तो असली मकसद ही यह है कि चालू खाता घाटे को खत्म किया जाए और इस तरह यह सुनिश्चित किया जाए कि चालू खाता घाटे के बराबर बने रहने की जिस स्थिति को हम प्रदत्त मानकर चल रहे हैं, उससे हमेशा के पीछा ही छूट जाए। दूसरे शब्दों में, तैरती विनिमय दर के ये पैरोकार किसी 'संतुलनकारी विनिमय दर' के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, जिसे पाने पर चालू खाता घाटा खत्म ही हो जाएगा। और वे इसमें विश्वास करते हैं कि अगर विनिमय दर को तैरते रहने दिया जाता है, वास्तविक विनिमय दर इस संतुलनकारी दर की ओर चली जाएगी।

संतुलित विनिमय दर की मरीचिका

बहरहाल, यह दलील पूरी तरह से बेतुकी है। किसी खास विनिमय दर पर (डालर के मुकाबले), किसी देश के माल विश्व बाजार में किसी अन्य देश की तुलना में कितने सफल होते हैं, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें, डालर के मुकाबले उस विनिमय दर पर, उस देश की वास्तविक मजदूरी दर तथा उसके, उसके द्वारा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी से लेकर, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक शामिल हैं और उसके प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए यही तुलनीय कारक शामिल हैं। यह आशा करना कि मुद्रा का विनिमय मूल्य तैरता छोड़ने से यह मूल्य खिसक कर किसी संतुलन की स्थिति की ओर बढ़ जाएगा, यह मानकर चलना है कि किसी मानीखेज अर्थ में ऐसा कोई संतुलन मौजूद है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि इन सभी कारकों को देखते हुए, जिनमें विनिमय की दर भी शामिल है, प्रतिस्पर्द्धी देशों से मुकाबले में, चालू खाता घाटे को खत्म करना विनिमय दर के इस हद तक अवमूल्यन का तकाजा करता है, जहां वास्तविक मजदूर वर्तमान स्तर से घटकर, चौथाई हिस्सा ही रह जाए। इस स्तर की वास्तविक मजदूरी शायद मजदूरों को स्वीकार्य तो नहीं ही होगी, हो सकता है कि यह गुजारे के स्तर से भी इतनी कम हो कि इस मजदूरी पर वे जिंदा ही नहीं रह सकते हों। बुनियादी तौर पर इसका अर्थ यह है कि कोई व्यावहारिक संतुलित विनिमय दर होती ही नहीं है। ऐसी कथित संतुलित अवस्था की उम्मीद में विनिमय दर को तैरते हुए नीचे की ओर जाने देने का, शायद कोई औचित्य ही नहीं होगा।

मजदूर वर्ग को भूखा मारने का नुस्खा

भारत में विनिमय दर को तैरते हुए, तीन दशक से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद, चालू खाता घाटे के खत्म होने के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर ऐसा भी नहीं है कि मजदूर इतनी बढ़ती हुई मजदूरी मांगते और हासिल करते रहे हैं कि, विनिमय दर में लगातार हो रही गिरावट को, बढ़ी हुई मजदूरी बेअसर करती रही हो।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पॉकेटफल एक्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00862)

बाल-अनुकूल एवं दिव्यांगजन अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

पडरौना, कुशीनगर।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुशीनगर के तत्वावधान में विकास खंड पडरौना के प्रसादपुर में बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं, मानसिक एवं बौद्धिक दिव्यांगता, शिक्षा के अधिकार, असंगठित श्रमिकों के अधिकार तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर संजीव कुमार त्यागी के कुशल मार्गदर्शन तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भुवन के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्राधिकरण द्वारा नालसा की विभिन्न योजनाओं एवं निःशुल्क कानूनी सेवाओं के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले भर में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रामवृक्ष गिरि ने बाल-अनुकूल कानूनी सेवाओं, मानसिक रूप से बीमार एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ÷बचों तथा मानसिक रूप से कमजोर या बीमार व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों के समान सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी कानूनी समस्या, मार्गदर्शन अथवा सहायता की आवश्यकता होने पर नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 का उपयोग करें। न्याय मित्र पवन कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। विद्यालय खुलने के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी अभिभावक अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। शिविर में अछैवर पासवान, विश्वनाथ यादव, मनीष कुमार, सुनैनी देवी, सुमन देवी, राजू प्रसाद, दुर्गा देवी, भागवत कुशवाहा, चैनमती देवी, सुनीता देवी, विश्वकला देवी, दिनेश प्रसाद, विनोद कुमार, रविंद्र प्रसाद सहित दो दर्जन से अधिक लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में विभिन्न विकास खंडों से आए श्रमिकों एवं ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई।

अस्पतालों के औचक निरीक्षण में 29 स्वास्थ्य कर्मी नदारद, जिलाधिकारी ने थमाया नोटिस

देवरिया।

ग्रामीण अंचलों में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था को पटरी पर लाने और सरकारी अस्पतालों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शुक्रवार सुबह ठीक 8:00 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) भागलपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ही केंद्रों पर भारी प्रशासनिक अराजकता और चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की मनमानी सामने आई। कलेक्ट्रेट की इस औचक कार्रवाई में दोनों अस्पतालों को मिलाकर कुल 29 स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी से गायब पाए गए, जिन्हें जिलाधिकारी ने सेवा नियमावली के तहत तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के विधिक निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सबसे पहले सीएचसी लार के मुख्य परिसर में प्रवेश किया। वहां सुबह के समय ओपीडी और प्रसव केंद्र जैसे संवेदनशील पटल खाली दिखे। जब कलेक्ट्रेट टीम ने वहां की आधिकारिक उपस्थिति पंजिका का विधिक मिलान किया, तो एक साथ 24 कर्मचारी और चिकित्सक कार्यस्थल से नदारद मिले।

इसे गंभीर प्रशासनिक शिथिलता मानते हुए जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई और प्रसव केंद्र में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने तथा शासन द्वारा अनुमन्य सभी सुविधाएं प्रसूताओं को मुहैया कराने की हिदायत दी। इसके तत्काल बाद जिलाधिकारी का काफिला पीएचसी भागलपुर पहुंचा। वहां भी प्रशासनिक लचरता चरम पर मिली, जहां 5 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सुरक्षा बाउंड्री वॉल कई जगहों से क्षतिग्रस्त मिली, जिसे खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के माध्यम से मनरेगा या अन्य मद से अविलंब ठीक कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, अस्पताल में लो-वोल्टेज की पुरानी समस्या और ट्रांसफार्मर न लग पाने के प्रशासनिक गतिरोध को देखते हुए विद्युत विभाग को नया ट्रांसफार्मर तत्काल स्थापित करने के विधिक निर्देश जारी किए गए। एक गंभीर विसंगति यह भी मिली कि स्टाफ नर्स के लिए आरक्षित एक सरकारी आवास में बिना किसी वैध आवंटन के अनधिकृत रूप से कब्जा जमाया गया था, जिसे प्रशासन ने तत्काल खाली कराने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने दोनों केंद्रों के प्रभारियों को आगाह किया है कि मरीजों को बाहर की दवाएं न लिखी जाएं और यदि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में दोबारा लापरवाही मिली, तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुबह 8 सीएचसी लार और पीएचसी भागलपुर पहुंचे जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी स्टाफ नर्स के सरकारी आवास पर अवैध कब्जे को खाली कराने और टूटी बाउंड्री वॉल को दुरुस्त करने के निर्देश

लियाफी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने सुधाकर चतुर्वेदी

- हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ निर्विरोध चुनाव
- गोरखपुर से पहली बार किसी को लियाफी में मिली उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की कमान

गोरखपुर। अखिल भारतीय अभिकर्ता संघ (लियाफी) का राष्ट्रीय अधिवेशन हैदराबाद में 16 से 18 जून तक आयोजित हुआ। इसमें देशभर के पांच हजार अभिकर्ता प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गोरखपुर के सुधाकर चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष चुने गए। पहली बार गोरखपुर के किसी अभिकर्ता को उत्तर-मध्य क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया है देशभर में लगभग 13.50 लाख एलआईसी अभिकर्ताओं के संगठन लियाफी के तीन वर्ष पर होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन और चुनाव में सुधाकर चतुर्वेदी को निर्विरोध क्षेत्रीय अध्यक्ष चुना गया। कानपुर के विजय कुमार सिंह क्षेत्रीय सचिव चुने गए। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कहा कि उत्तर मध्य क्षेत्र में 2.85 लाख अभिकर्ताओं की उम्मीदें हैं कि अभिकर्ताओ के लिए स्वास्थ्य बीमा भुगतान मंडल स्तर पर किया जाए। रूप इंश्यारेस बढ़ाए जाने, पेंशन योजना, एजुकेशनल सेमिनार मंडल स्तर पर किए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनके निर्वाचन पर पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान पांडेय, संजय सिंह, शैलेंद्र मिश्र, उमेश चंद रघु, संजय तिवारी, राजेश चौहान, राम विनय पांडेय, राम चंद्र शुक्ल, शंकनाथ शर्मा, अवधेश चौबे, प्रमोद मिश्र, डॉ. जय प्रकाश वर्मा, सुरेश श्रीवास्तव व वशिष्ठ पांडेय आदि ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

शहीद विजय मौर्य स्मारक स्थल पर चला स्वछता अभियान

भटनी देवरिया।

भटनी क्षेत्र के छपिया जयदेव ग्राम सभा स्थित शहीद विजय मौर्य स्मारक स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वछता अभियान चलाया। कार्यक्रम की शुरुआत बूथ कमेटी की बैठक से हुई, जिसके बाद स्मारक परिसर में उगी झाड़ियों व घास की साफ-सफाई की गई। बताया गया कि कुछ समय से गेट बंद होने के कारण नियमित सफाई कार्य प्रभावित था। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री दीपक मल्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से संपर्क, स्वछता अभियान तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संयोजन केएस एकेडमी के प्रबंधक व युवा भाजपा नेता शिवप्रताप सिंह राजन ने किया।

दीपक मल्ल के नेतृत्व में जुटे भाजपा कार्यकर्ता, बैठक के साथ किया वृक्षारोपण

इस दौरान शक्ति केंद्र प्रमुख सतेन्द्र कुशवाहा, बूथ अध्यक्ष अजय मिश्रा, वीरेंद्र कुशवाहा, शहीद विजय मौर्य के चाचा शुभलाल मौर्य, अभिषेक सिंह, मुकेश पटेल, अजीत सिंह कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, प्रिंस गौंड, अवधेश प्रसाद सहित कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे।

अंतर्जनपदीय अवैध शराब तस्करी गैंग का भंडाफोड़, 319 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

पडरौना, कुशीनगर। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पडरौना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 37 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, एक थ्री-व्हीलर वाहन तथा एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब और वाहन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 4.31 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 18/19 जून की रात कोतवाली पडरौना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रामकोला रोड की ओर एक थ्री-व्हीलर में अवैध शराब ले जाई जा रही है।

मोहर्रम को लेकर थवई टोला में शांति समिति की बैठक

- ताजियादारों व ग्रामीणों को प्रशासनिक निर्देशों से कराया गया अवगत

भटनी देवरिया। आगामी मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से भटनी थाना क्षेत्र के घाटी चौकी अंतर्गत थवई टोला में ताजियादारों एवं ग्रामवासियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को उच्च अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। मोहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपसी भाईचारा कायम रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को दें। बैठक में ताजियादारों, संभ्रांत नागरिकों एवं ग्रामीणों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

मोहर्रम को लेकर प्रशासन सख्त, भटनी थाने में डीजे संचालकों को दी गई कड़ी चेतावनी

भटनी देवरिया।

- मानक से अधिक ध्वनि व भड़काऊ गीतों पर होगी कार्रवाई, शांति बनाए रखने की अपील

आगामी मोहर्रम पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से भटनी थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी की मौजूदगी में डीजे संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहार के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों और प्रशासनिक निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि डीजे निर्धारित ध्वनि मानक के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा राष्ट्र विरोधी गीतों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने कहा कि त्योहार आपसी भाईचारे और शांति का प्रतीक है, इसलिए सभी आयोजक प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। बैठक में पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

रिश्वतखोरी के आरोप में लेखपाल रजनीश मिश्र निलंबित

देवरिया। जनता दर्शन में मिली रिश्वतखोरी की शिकायत और साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सलेमपुर तहसील के हल्का लेखपाल रजनीश मिश्र को अनुचित धनउगाही और न्यायालय के आदेश की अनदेखी करने के आरोप में उप जिलाधिकारी सलेमपुर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई से तहसील क्षेत्र के भ्रष्ट और लापरवाह कर्मियों में हड़कंप मच गया है। निलंबित लेखपाल को रजिस्ट्रार कानूनगो (भूलेख) कार्यालय सलेमपुर से संबद्ध किया गया है। विगत दिनों जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के जनता दर्शन कार्यक्रम में ग्राम सोनवर्षा (तप्पा सलेमपुर) निवासी पीड़ित श्री प्रकाश यादव ने उपस्थित होकर शिकायती पत्र दिया था।

पीड़ित का आरोप था कि हल्का लेखपाल रजनीश मिश्र ने काम के एवज में उनसे रिश्वत ली, लेकिन इसके बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किया और उल्टे अधिक धन की मांग करने लगे। पीड़ित ने अपनी शिकायत के समर्थन में लेखपाल द्वारा धन लेते समय बनाई गई एक वीडियो क्लिपिंग भी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने इसकी जांच तत्काल मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) को सौंप दी थी। मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा की गई त्वरित जांच में आरोपी लेखपाल रजनीश मिश्र न्यायालय के एक आदेश का स्थलीय अनुपालन न कराने तथा अवैध उत्कोच (रिश्वत) लेने के विधिक दोषी पाए गए। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होते ही जिलाधिकारी के कड़े निर्देश पर उप जिलाधिकारी सलेमपुर ने निलंबन की यह विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। पूरे मामले की विस्तृत और गहन जांच के लिए तहसीलदार सलेमपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे।

जनता दर्शन में पीड़ित ने डीएम के सामने पेश की थी रिश्वत लेने की वीडियो क्लिपिंग

सर्दियों में प्रदूषण रोकने को दिल्ली में अभी से तैयारी- नवंबर से इन वाहनों पर बैन, दोगुनी होगी पार्किंग फीस

नई दिल्ली। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रतिबंध लगाने के बजाय दिल्ली सरकार ने नवंबर से फरवरी तक लागू होने वाली शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। इसके तहत वाहनों, निर्माण गतिविधियों, पार्किंग, कार्यालयों और खुले में जलाने जैसी गतिविधियों पर पहले से नियंत्रण के उपाय तय किए गए हैं। अब तक दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैप के तहत पाबंदियां लागू की जाती थीं, जिससे आम लोगों, व्यापारियों और संस्थानों को अचानक बदलावों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता था। नई व्यवस्था में सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि नवंबर से फरवरी के बीच खराब हवा की स्थिति बनने पर कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इससे नागरिकों, आरडब्ल्यूए, उद्योगों, निर्माण एजेंसियों और सरकारी विभागों को पहले से तैयारी करने का समय मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) होगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी। सर्दियों के दौरान निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही यातायात दबाव घटाने के लिए चरणबद्ध कार्यालय समय की व्यवस्था लागू की जा सकती है। सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत भौतिक उपस्थिति और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान रखा गया है। जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट मिलेगी।

दिल्ली में निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों से निकलने वाली धूल को प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए सरकार ने परियोजना संचालकों और निर्माण एजेंसियों को पहले से अपनी योजना तैयार करने को कहा है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण कार्यों को पर्यावरणीय मानकों और धूल नियंत्रण उपायों के साथ करना होगा। वहीं 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच, जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन, मिस्ट सिस्टम और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को अनिवार्य किया जाएगा।

बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल जारी
थमी मुंबई की रफ्तार; यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

प्रशासन की ओर से मांगों पर ठोस आश्वासन न मिलने के कारण कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस हड़ताल के चलते लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेस्ट की सार्वजनिक बस सेवा, जो प्रतिदिन लगभग 25 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान करती है, इस हड़ताल से लगभग ठप हो गई है। यात्रियों को अब मेट्रो, टैक्सी और ऑटो रिक्शा जैसे अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

मुंबई। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) के कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन था। प्रशासन की ओर से मांगों पर ठोस आश्वासन न मिलने के कारण कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस हड़ताल के चलते लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेस्ट की सार्वजनिक बस सेवा, जो प्रतिदिन लगभग 25 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान करती है, इस हड़ताल से लगभग ठप हो गई है। यात्रियों को अब मेट्रो, टैक्सी और ऑटो रिक्शा जैसे अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती के संयोजक उदय आम्बोणकर ने बताया कि कोई ठोस निर्णय न होने की स्थिति में, उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। कर्मचारियों की इस हड़ताल से मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है।

बस सेवा पर पड़ा क्या असर?
बेस्ट के बेड़े में कुल 2,766 बसें हैं, जिनमें से 2,517 निजी ऑपरेटरों से लीज पर ली गई हैं। हड़ताल के कारण, शुक्रवार को सड़कों पर केवल 48 बसें ही चल सकीं। दिन के पहले भाग में केवल 38 बसें ही सड़कों पर उतरीं, लेकिन पथराव की घटनाओं के कारण छह बसों को डिपो वापस लौटना पड़ा। कई यात्रियों को हड़ताल की जानकारी बस स्टॉप पहुंचने के बाद ही मिली। टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा मनमाने ढंग से अधिक किराए वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आईं, खासकर रेलवे स्टेशनों के बाहर।

खास तौर से किन पर पड़ा असर?
मरीज और तीमारदार- केईएम अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों में जाने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सामान्यतः वे उपनगरीय ट्रेनों से दादर या परेल जाकर बेस्ट बस पकड़ते थे, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें टैक्सी के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा।
स्कूल छात्र – बसों की अनुपलब्धता के कारण, अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए व्यक्तिगत वाहनों का सहारा लेना पड़ा।
परिवहन के वैकल्पिक साधनों पर बोझ- बेस्ट बस सेवा मुंबई में उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन साधन है, जो प्रतिदिन लगभग 75 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। बेस्ट बसें हर दिन लगभग 25 लाख यात्रियों को अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं।

मेट्रो में यात्रियों की बढ़ी तादात
इस हड़ताल का सीधा असर मेट्रो सेवाओं पर पड़ा। महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार, शुक्रवार शाम 7 बजे तक विभिन्न मेट्रो कॉरिडोर पर कुल 2,48,453 यात्रियों ने यात्रा की, जो पिछले दिन की तुलना में 13,860 अधिक थी। मेट्रो लाइन 3 पर भी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, इस कॉरिडोर पर शाम 7 बजे तक 1,81,716 यात्रियों ने यात्रा की, जो गुरुवार के 1,51,502 यात्रियों से 30,214 अधिक है। मुंबई मेट्रो वन के घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा कॉरिडोर पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई।

हड़ताल में पथराव वगैरह की घटनाएं
बेस्ट के प्रवक्ता के अनुसार, शाम तक हड़ताल से संबंधित 26 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें पथराव की 10 घटनाएं, कर्मचारियों को धमकी देने के 10 मामले, बस के शीशे टूटने के तीन मामले और बसों के टायरों से हवा निकालने के तीन मामले शामिल हैं।

खतरे में अमेरिका-ईरान शांति समझौता
लेबनान पर इस्राइल ने बरसाए बम, तेहरान ने बातचीत रोकी

नई दिल्ली। लेबनान में इस्राइली सेना की कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर से भड़कने की आशंका है। दरअसल, 111 दिनों के संघर्ष के बाद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर समझौता हुआ है। इस्लामाबाद एमओयू के नाम से हुए इस समझौते को मानने से इस्राइल ने इनकार कर दिया है। इस्राइली सेना ने शुक्रवार को रात भर दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्राइल की तरफ से हमला होने के बाद हिजबुल्ला ने इस्राइल पर जबरदस्त पलटवार भी किया है।

लेबनान को लेकर क्या मांग कर रहा ईरान?
ईरान का कहना है कि दक्षिणी लेबनान पर इस्राइल के हमले बंद होने के साथ कब्जा भी खत्म होना चाहिए। दूसरी तरफ इस्राइल का कहना है कि ईरान समर्थित शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह के कारण खतरा बना हुआ है। इस कारण सेना पीछे नहीं हटेगी। इस्राइल की दलील है कि हिजबुल्ला से लड़ने के लिए उसे पूरी आजादी चाहिए, क्योंकि इसके लड़ाके उत्तरी इस्राइल पर हमले करते रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इस्राइली हमले में एक और व्यक्ति की मौत के बाद मरने वाले लोगों की संख्या 18 पहुंच गई है। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार आधी रात से हमले जारी हैं। इस्राइली ड्रोन से हमले कर रहा है। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, आधी रात के बाद हमलों में 33 अन्य लोग घायल भी हुए हैं।

खुला होर्मुज जलमार्ग, टोल टैक्स पर फंसा पेंच; शिपिंग इंडस्ट्री की थमी सांसें
अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन भविष्य में ईरान की ओर से टोल टैक्स लगाए जाने की आशंका पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल, शिपिंग और ऊर्जा सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत शुरुआती 60 दिनों के लिए जहाजों कोबिना किसी शुल्क के सुरक्षित मार्ग की गारंटी दी गई है, लेकिन इस अवधि के बाद जलमार्ग के स्थायी प्रशासन और समुद्री सेवाओं को तय करने के लिए ईरान, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के बीच होने वाली आगामी त्रिपक्षीय वार्ता पर दुनिया भर के जहाज मालिकों और ऊर्जा कंपनियों की नजरें टिकी हुई हैं।

नीतीश पर झूठे आरोप! लालू यादव के सुरक्षा दावों को जेडीयू ने नकारा, बोले - यह सिर्फ सियासत

पटना। जदयू ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दी गई सुरक्षा कम करने के बिहार सरकार के फैसले के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ था। लालू की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार सत्ता में थे, वे राबड़ी देवी के घर पर रहे। अब जब सरकार ने उन्हें अलग और सही घर दिया है, तब भी वे दबाव की राजनीति कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नीतीश ही यह सब करवा रहे हैं। सुरक्षा और घर से जुड़े फैसलों में राजनीतिक दखल के आरोपों को खारिज करते हुए चौधरी ने कहा कि सुरक्षा समिति और पुलिस विभाग ऐसे फैसले स्वतंत्र रूप से लेते हैं। बुधवार को लालू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और JD(U) प्रमुख नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा कम करने के बिहार सरकार के फैसले के लिए वही जिम्मेदार हैं। हाल ही में, एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू और राबड़ी देवी की Z-प्लस सुरक्षा कम कर दी थी और उन्हें 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी घर खाली करने का निर्देश दिया था। एक और मंत्री, मदन साहनी ने कहा कि लालू लगभग 20 साल तक उस घर में रहे और उस दौरान किसी ने भी उनसे घर खाली करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब जब सरकार बदल गई है, तो यह मामला भवन निर्माण विभाग और सुरक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। लालू जी को इस मामले में नीतीश का नाम नहीं लेना चाहिए था। बिहार पुलिस ने यह भी साफ किया कि नए नियमों के अनुसार लालू और राबड़ी देवी दोनों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में पुलिस ने कहा कि दोनों नेताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था तय प्रावधानों के अनुसार बनाए रखी जा रही है। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (एसएसजी) एक्ट, 2010 के तहत लालू को बॉडीगार्ड, घर पर गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, एक पायलट गाड़ी और बैलिस्टिक-रेसिस्टेंट गाड़ी दी गई है। अतिरिक्त निगरानी के लिए सादे कपड़ों में स्पेशल ब्रांच के जवान भी तैनात किए गए हैं।

पीएम मोदी का बंगाल दौरा, किसानों को देंगे बड़ी सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वे पश्चिमबंग दिवस (पश्चिम बंगाल दिवस) में शामिल होंगे और 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। 20 जून को दोपहर लगभग 3:45 बजे, प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह जगह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई है। राज्य के कार्यक्रम की थीम पश्चिम बंगाल- विरासत, सद्भाव और विकास है, जो राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकास के लक्ष्यों को दर्शाती है। इस कार्यक्रम के दौरान, मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत देश भर के 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधे 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अकेले पश्चिम बंगाल में, 45 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा की जाएगी, जिससे राज्य में कुल बांटी गई राशि 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर, 2019 से इस योजना के तहत बांटी गई कुल राशि 4.46 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। मोदी राज्य में कई अहम केंद्रीय कृषि योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल है। PMFBY का मकसद लगभग 14 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती करने वाले करीब 50 लाख किसानों को फसल बीमा कवर देना है। इसमें लगभग 28,140 करोड़ रुपये की बीमित फसल का मूल्य शामिल है और इसके लिए भारी प्रीमियम सब्सिडी दी जाएगी।

*योग दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा

21 जून को कोलकाता में, प्रधानमंत्री मोदी रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। वे वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे और हजारों योग करने वालों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में हिस्सा लेंगे। 2026 के लिए थीम है स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग। यह थीम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक भलाई, भावनात्मक मजबूती और सक्रिय रूप से उम्र बढ़ने में योग की भूमिका पर जोर देती है, जो बढ़ती जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ व सम्मानजनक तरीके से उम्र बढ़ने पर दिए जा रहे ध्यान के अनुरूप है। जब से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया है, तब से प्रधानमंत्री ने देश और विदेश में कई जगहों पर इन कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। 2026 में योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन और पोस्ट शामिल हैं। यह योग को स्वास्थ्य और सद्भाव के एक वैश्विक आंदोलन के रूप में रेखांकित करता है।

राहुल 56 साल के हुए, पीएम मोदी खरगे समेत कई नेताओं ने दी बधाई

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर शुक्रवार को उन्हें बधाई दी और कहा कि वह सत्ता के सामने निर्भीक होकर सच कहते हुए समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की ज्येष्ठ संतान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

खरगे बोले- आपका अडिग संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत
वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सदस्य और निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह पिछले 22 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं। खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और वंचित एवं अनसुनी आवाजों के लिए आपका अडिग संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। समावेशिता, सामाजिक न्याय, सद्भाव और करुणा की कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली परंपरा आपके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है।

सदैव समाज के सबसे कमजोर हितों की सशक्त पैरवी की
उन्होंने कहा कि जनता के बीच राहुल गांधी के निरंतर संवाद और सत्ता से निर्भीक होकर सच कहने के साहस के माध्यम से आपने सदैव समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों और हितों की सशक्त पैरवी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शक्ति और राष्ट्रसेवा के लिए दीर्घायु जीवन प्रदान करें।

ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाते हैं- पवन खेड़ा
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, बहुत कम नेताओं ने इतने लंबे समय तक इतनी कटुता भरी आलोचना और इतने लंबे समय तक निरंतर सार्वजनिक जांच परख का सामना किया है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग सार्वजनिक जीवन से पीछे हट जाते। लेकिन उन्हें कमजोर करने का हर प्रयास मानो उनके संकल्प को और दृढ़ करता गया, उनकी राजनीति को और परिपक्व बनाता गया, और जनता से उनके संबंध को और गहरा करता गया।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति राहुल गांधी की अटूट प्रतिबद्धता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा, महिलाओं और वंचित वर्गों के धुर समर्थक राहुल आज पूरे भारत में उन लोगों की सशक्त आवाज बन चुके हैं, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है।

उन्होंने कहा कि संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के प्रति राहुल गांधी की अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करती है। गहलोत ने कहा, मैं उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं राष्ट्रसेवा के लिए अटूट संकल्प और ऊर्जा की कामना करता हूं।

यह मुंबई हमारी है- उद्धव ठाकरे

शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर उद्धव गुट ने विरोधियों को दिया संदेश, गिनाई उपलब्धियां

मुंबई। शिवसेना की स्थापना को आज 60 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट ने विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है। पार्टी का कहना है कि पिछले छह दशकों में उसे तोड़ने और कमजोर करने की बहुत कोशिशें हुईं। विरोधियों के मन में शिवसेना का इतना डर था कि उन्होंने समय-समय पर कई समानांतर संगठन बनाए, लेकिन वे सब खत्म हो गए। बालासाहेब ठाकरे ने जो नींव रखी थी और जो विचारधारा स्थापित की थी, वह आज भी मजबूती से खड़ी है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में हालिया बगावत पर तीखा निशाना साधा गया है। इसमें कहा गया कि आज व्यावसायिक सोच वाले कई नकली संगठन खड़े किए जा रहे हैं। शिवसेना की स्थापना कभी किसी व्यापारिक सौदे के लिए नहीं हुई थी। बालासाहेब ने पार्टी को कभी कारोबार नहीं बनने दिया। इसीलिए समय-समय पर उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जो केवल सौदेबाजी और अवसर की तलाश में थे। इससे मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की धारा शुद्ध बनी रही, जिसकी गूंज आज भी पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देती है। संपादकीय के अनुसार, शिवसेना ने मराठी समाज को स्वाभिमान से जीना सिखाया। लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वे गर्व से कह सकें, यह मुंबई हमारी है। पार्टी ने आम लोगों को पार्षद और नेता बनाया। शिवसेना की शाखाओं का नेटवर्क जनता के लिए किसी पारिवारिक अदालत की तरह काम करता था। शिवसैनिकों ने सड़क, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी समस्याओं के समाधान के लिए दिन-रात काम किया। किसी भी अन्याय या दुर्घटना के समय शिवसैनिक ही सबसे पहले मौके पर पहुंचते थे। उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान को खत्म करने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। पार्टी को शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है। संपादकीय में बालासाहेब ठाकरे की उस बात का जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पीठ पर इतने घाव हो चुके हैं कि अब नई जगह नहीं बची। इसके बावजूद शिवसेना हर बार सहकर आज इस मुकाम पर है क्योंकि विरोधियों में सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। शिवसेना ने समाजसेवा के साथ-साथ हिंदुत्व का शंखनाद भी किया। मलंगगढ़ से लेकर अयोध्या आंदोलन तक पार्टी ने बड़े बलिदान दिए। संपादकीय में सवाल पूछा गया कि क्या आज खुद को हिंदुत्व का समर्थक बताने वाले लोग शिवसेना के योगदान का थोड़ा हिस्सा भी दे पाए हैं? पार्टी ने हमेशा राष्ट्र प्रथम के मंत्र को माना है। अंत में कहा गया कि जैसे शिवाजी महाराज ने हिंदुओं की पहचान बनाई, उसी विरासत को बालासाहेब ने आगे बढ़ाया। शिवसेना अमर है।

जब तक जीत नहीं जाते, हम और डीएमके साथ लड़ेंगे- राहुल गांधी

अपने 56वें जन्मदिन पर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए एक अहम राजनीतिक साझेदारी को जारी रखने का संकेत दिया। उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का शुक्रिया अदा किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनके साझा संकल्प पर जोर दिया। विपक्षी गठबंधन के लिए यह सार्वजनिक संदेश एक अहम मोड़ पर आया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में, गांधी ने गठबंधन को भरोसा दिलाते हुए लिखा- आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, थिरु एम.के. स्टालिन। भारत की सोच, हमारे संविधान और संघवाद की रक्षा करने का हमारा साझा संकल्प हमें आगे भी राह दिखाता रहेगा - यह हमारी लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है, और हम इसे जीत मिलने तक मिलकर लड़ेंगे।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) प्रमुख एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल शुक्रवार को 56 साल के हो गए। विजय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल को अपना प्रिय भाई बताया और जनसेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की।